

अनुक्रमणिका

| क्र. सं. | टॉपिक का नाम |
|----------|---|
| 1. | राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट : सिलारपुर |
| 2. | राज उन्नति की 5वीं बैठक |
| 3. | भिवाड़ी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) |
| 4. | 'राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव' का तीसरा संस्करण |
| 5. | न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. हाई-डोज रेट ब्रेकीथेरेपी सुविधा : बीकानेर 2. 'जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप' में राजस्थान का प्रदर्शन 3. अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशू (पुरुष एवं महिला) चैंपियनशिप 4. अभिमन्यु निरबान को 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार-एआई एण्ड मार्केटिंग' 5. स्वगणना में जयपुर और सीकर सबसे आगे 6. न्यायाधीश मदन लाल भाटी |
| 6. | थोक मूल्य सूचकांक (WPI) |
| 7. | तड़ितझंझा (Thunderstorm) |
| 8. | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) |
| 9. | लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई): भारत के समावेशी विकास की रीढ़ |
| 10. | नई वैश्विक अव्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता |
| 11. | थ्यूसीडाइड्स ट्रैप |
| 12. | 'कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट' (CCRA) |
| 13. | काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (CAR-T Cell) थेरेपी |



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट : सिलारपुर



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भिवाड़ी के खुशखेड़ा स्थित सिलारपुर में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया।

राजस्थान को मिला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट



: सिलारपुर :

राजस्थान की नई पहचान
तकनीक की नई उड़ान



राजस्थान का पहला
सेमीकंडक्टर प्लांट



औद्योगिक विकास को
मिलेगी नई गति



हजारों लोगों को मिलेगा
रोजगार के अवसर



आत्मनिर्भर भारत की दिशा में
राजस्थान का बड़ा कदम



हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग
की नई शुरुआत



निवेश, नवाचार और
विकास का नया केंद्र



मेक इन इंडिया को
मिलेगी मजबूती



मुख्य बिन्दु:

- **पेरेंट कंपनी :** मैसर्स सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड।
- **विकास :** यह ELCINA द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) है।
- यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम (SME) है, जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया है।
- इसी के साथ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत भारत में अब कुल 12 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
- **विस्तार :** सिलारपुर (भिवाड़ी) में इस क्लस्टर को 50.3 एकड़ ज़मीन पर ₹46.09 करोड़ की परियोजना लागत से विकसित किया गया है।
- **भारत सरकार द्वारा प्रदान सहायता :** इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) योजना के तहत ₹20.24 करोड़ की प्रत्यक्ष सहायता।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की SPECS (स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स) योजना के तहत विकसित यह प्लांट ₹150 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ स्थापित किया गया है।
- **निर्माण :** इस प्लांट में Micro SD और फ्लैश स्टोरेज जैसे उत्पादों के लिए मेमोरी चिप्स, LED ड्राइवर ICs, SIMs और RFID उत्पादों की पैकेजिंग की जाएगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी - 2025 (राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति)

- **अनुमोदन :** राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा 21 जनवरी, 2026 को।
- **विमोचन :** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 18 मार्च, 2026 को जयपुर से।
- **उद्देश्य :** राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाना।

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



- साथ ही, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना।
- पॉलिसी के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डवलपमेंट तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- नीति में सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत-प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है।
- 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति।
- कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट।

--:4::--

राज उन्नति की 5वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

- 15 मई, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जयपुर में 'राज उन्नति की पाँचवीं बैठक' आयोजित की गई।



मुख्य बिन्दु:

- राज उन्नति का पूरा नाम : राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन (Raj-UNNATI)।
- राज-उन्नति राजस्थान सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित शुरू की गई एक प्रशासनिक शासन और परियोजना निगरानी पहल है।

--:5:--

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



- इसके माध्यम से मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से सीधा संवाद कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा समस्या का वास्तविक समाधान किया जाता है।
- राजस्थान इस मॉडल को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार के इस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ नवाचार के रूप में मान्यता मिली है।
- **प्रथम बैठक** : 17 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जयपुर में 'राज उन्नति' की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **PM-PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation)** को वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ताकि परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों को टेक्नोलॉजी-आधारित मॉनिटरिंग और समयबद्ध समाधान के साथ लागू किया जा सके।
- **त्रि-स्तरीय प्रणाली** : इसमें सेवा तीर्थ (PMO), केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं।

--:6:--

भिवाड़ी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा भिवाड़ी में 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)' की स्थापना के लिए ₹75 करोड़ के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की गई।

COMMON EFFLUENT TREATMENT PLANT (CETP)



PHYSICAL - CHEMICAL - BIOLOGICAL TREATMENT PROCESS

मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि 'कहरानी ग्रीन ट्रीटर्स एसोसिएशन' द्वारा 6 मेगालीटर प्रति दिन (MLD) क्षमता का CETP स्थापित किया जाएगा।
- सहयोग :** उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा।

--7--

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (राजस्थान) द्वारा राज्य में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु 'एकीकृत CETP की स्थापना और मौजूदा CETP के उन्नयन के लिए संशोधित योजना' लागू की गई है।
- इस योजना में नया CETP स्थापित करने या स्थापित CETP को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹75 करोड़ तक अनुदान दिया जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)

- कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) एक केंद्रीकृत सुविधा है, जिसे एक विशिष्ट औद्योगिक समूह के भीतर स्थित कई उद्योगों से अपशिष्ट जल को एकत्र करने, उपचारित करने और सुरक्षित रूप से निर्वहन या पुनर्चक्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपचार प्रक्रिया:

- **प्रारंभिक उपचार :** यह बड़े ठोस मलबे, रेत को छानकर अलग करता है और आने वाले अपशिष्ट जल के pH (Potential of Hydrogen) और तापमान को नियंत्रित करता है।
- **प्राथमिक उपचार :** इसमें अवसादन और जमाव जैसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है और तेल और ग्रीस की मात्रा को कम किया जाता है।
- **द्वितीयक (जैविक) उपचार :** कार्बनिक संदूषकों को तोड़ने और जैविक और रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) और (COD) को कम करने के लिए विशेष बैक्टीरिया और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है।
- **तृतीयक उपचार :** उन्नत निस्पंदन, कार्बन अवशोषण और कीटाणुशोधन पानी को शुद्ध करने के लिए ताकि यह सुरक्षित निर्वहन या पुनः उपयोग मानकों को पूरा कर सके।

'राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव' का तीसरा संस्करण

चर्चा में क्यों?

- 15 मई, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव - 2026' का उद्घाटन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- विषयवस्तु (Theme) : 'Shaping India's New Energy Economy'
- आयोजन : ईटी गवर्नमेंट (ETGovernment) द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) के सहयोग से।
- आयोजन स्थल : जयपुर के होटल मैरियट में।
- उद्देश्य : राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को गति देना, हरित ऊर्जा (अक्षय ऊर्जा) के विकास को बढ़ावा देना और प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर व पवन ऊर्जा) के बुनियादी ढाँचे में निवेश को आकर्षित करना।

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की संभावना : 828 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट (GW) पवन ऊर्जा।
- नोट : अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है।
- लक्ष्य : राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट (GW) अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट (GW) की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना : इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024:

- राज्य सरकार द्वारा इस नीति की अधिसूचना 04 दिसंबर, 2024 को जारी की गई।
- नीति की अवधि: यह नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है और 29 मार्च, 2029 तक या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित करने तक लागू रहेगी।

लक्ष्य:

- नीति का उद्देश्य राज्य में वर्ष 2029-30 तक 1,25,000 मेगावाट (125 गीगावाट) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

125 गीगावाट का विभाजन:

| क्रम | उत्पादन का प्रकार | लक्षित क्षमता |
|------|--|---------------|
| 1. | सौर (Solar) | 90,000 MW |
| 2. | पवन और हाइब्रिड (Wind & Hybrid) | 25,000 MW |
| 3. | हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (PSP), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम | 10,000 MW |

- नोट: राजस्थान द्वारा परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 54,000 मेगावाट से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2031-32 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

--:10:--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

| क्र. सं. | न्यूज़ |
|----------|---|
| 1. | <p>हाई-डोज रेट ब्रैकीथेरेपी सुविधा : बीकानेर</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के PBM अस्पताल स्थित आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक हाई-डोज रेट ब्रैकीथेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया।यह अत्याधुनिक मशीन 'टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर योजना' के अंतर्गत लगाई गई है।हाई-डोज रेट (HDR) ब्रैकीथेरेपी एक उन्नत आंतरिक विकिरण उपचार है, जो प्रोस्टेट, स्तन, स्त्री रोग (सर्वाइकल) और त्वचा के कैंसर के लिए ट्यूमर के अंदर कम समय में उच्च विकिरण (12 Gy/घंटे से अधिक) पहुंचाता है।इसमें इरिडियम-192 जैसे रेडियोधर्मी स्रोत का उपयोग किया जाता है।नई HDR ब्रैकीथेरेपी यूनिट का उपयोग मुख्य रूप से स्त्री रोग संबंधी कैंसरों में किया जाएगा, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के उपचार को "गोल्ड स्टैंडर्ड" माना जाता है। |
| 2. | <p>'जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप' में राजस्थान का प्रदर्शन</p> <ul style="list-style-type: none">यश कुमार (भरतपुर), स्वर्ण पदक : 33 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के बॉक्सर को हराकर स्वर्ण पदक जीता।एंजल बागराणा (जोधपुर), स्वर्ण पदक : फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। |
| 3. | <p>अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बुशू (पुरुष एवं महिला) चैंपियनशिप</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : 3 से 9 मई, 2026 तक कश्मीर विश्वविद्यालय (श्रीनगर) में।राजस्थान का प्रदर्शन : राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम ने इस चैंपियनशिप में कुल 8 पदक (5 रजत और 3 कांस्य) जीते।रजत पदक : भानु प्रताप पारीक (कियानशु), तनीषा महावर (शुआंगज्यान), महिमा चौधरी (ट्रेडिशनल नान टाइप), गौरांग सैनी (विंग चुन) और वैदेही पारीक (फ्लेक्सिबल वेपन)।कांस्य पदक : वैदेही पारीक (ट्रेडिशनल नान टाइप), पीयूष मेहरा (ताइजी टाइप इवेंट) और पूजा (सांडा स्पर्धा)। |

| | |
|----|---|
| 4. | <p>अभिमन्यु निरबान को 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार-एआई एण्ड मार्केटिंग'</p> <ul style="list-style-type: none">■ 'भारत इनोवेशन्स' के संस्थापक अभिमन्यु निरबान को नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आयोजित एक समारोह में 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार - एआई एण्ड मार्केटिंग' से सम्मानित किया गया है।■ संबंधित ज़िला : सीकर।■ 'भारत इनोवेशन्स' को भारत की पहली समर्पित AI मार्केटिंग एजेंसी के रूप में जाना जाता है। |
| 5. | <p>स्वगणना में जयपुर और सीकर सबसे आगे</p> <ul style="list-style-type: none">■ जनगणना - 2027 के तहत राजस्थान में आयोजित डिजिटल स्वगणना (Self Enumeration) में जयपुर जिला पहले स्थान पर और सीकर जिला दूसरे स्थान पर रहा।■ स्व-गणना की अवधि : 1 से 15 मई, 2026 तक।■ स्व-गणना सुविधा का उद्देश्य कार्यरत, व्यस्त अथवा सुविधा अनुसार स्वयं विवरण उपलब्ध कराने के इच्छुक परिवारों को डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी भरने का अवसर प्रदान करना है। |
| 6. | <p>न्यायाधीश मदन लाल भाटी</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया।■ नियुक्ति : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा।■ आयोग का उद्देश्य : यह आयोग राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जातियों को न्यायसंगत राजनैतिक आरक्षण देने का मैकेनिज्म और सिफारिशें तय करने के लिए कार्य करेगा। |



थोक मूल्य सूचकांक (WPI)



चर्चा में क्यों?

- पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अप्रैल 2026 में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 3.5 साल के उच्च स्तर 8.3% तक पहुँच गई।



मुख्य बिन्दु:

थोक मूल्य सूचकांक (WPI):

- अर्थ:** यह एक निश्चित अवधि के दौरान घरेलू बाजार में वाणिज्यिक लेनदेन के तहत थोक बिक्री के प्रथम बिंदु पर वस्तुओं के एक निश्चित समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने वाला सूचकांक है।

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



- **जारीकर्ता:** इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
- **आधार वर्ष:** 2022-23
- **बास्केट की संरचना:** इसे तीन प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
 - I. **प्राथमिक वस्तुएं (भारांश 22.62%):** इसमें 4 उप-समूह शामिल हैं: खाद्य वस्तुएं, गैर-खाद्य वस्तुएं, खनिज और कच्चा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस।
 - II. **ईंधन और ऊर्जा (भारांश 13.15%):** इसमें 3 उप-समूह शामिल हैं: कोयला, खनिज तेल, विद्युत।
 - III. **विनिर्मित उत्पाद (भारांश 64.23%):** इसमें 22 उप-समूह शामिल हैं।

UTKARSH

CIVIL SERVICES

भूगोल एवं भू-विज्ञान

तड़ितझंझा (Thunderstorm)

चर्चा में क्यों?

- उत्तर प्रदेश में बेमौसम आंधी-तूफान (तड़ितझंझा) की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। तड़ितझंझा कम अवधि के अत्यधिक तेज स्थानीय तूफान होते हैं, जो छोटे क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन अत्यंत विनाशकारी होकर जनजीवन और अवसंरचनाओं को भारी नुकसान पहुँचाते हैं।



मुख्य बिन्दु:

तड़ितझंझा

- तड़ितझंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करता है। तड़ितझंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं।
- ये मेसो-गामा मौसम प्रणालियों की श्रेणी में आते हैं, जिनका स्थानिक विस्तार लगभग 2 से 20 किलोमीटर तक होता है और लगभग कुछ घंटों तक सक्रिय रहते हैं।

--:15:--

- **प्रकार:** तड़ितझंझा की प्रबलता या तीव्रता को देखते हुए, इन्हें भारत में निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:
 - **सामान्य तड़ितझंझा:** बिजली की चमक के साथ बादलों की तेज गड़गड़ाहट, सामान्य से भारी बारिश और 29 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे का अधिकतम पवन वेग।
 - **भयानक तड़ितझंझा:** निरंतर गर्जना और कभी-कभी ओलावृष्टि, और अधिकतम पवन वेग 74 किमी प्रति घंटा से अधिक।

- **घटना:** इनकी आवृत्ति और तीव्रता गर्मियों के महीनों (मार्च से जून) में सर्वाधिक होती है, क्योंकि इस समय सतह स्तर पर वायुमंडल अत्यधिक गर्म हो जाता है।

तड़ितझंझा का जीवन चक्र

- **विकासशील चरण:** तड़ितझंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्वप्रवाह है, जिसके कारण कपासी बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊँचाई तक पहुँचते हैं। ये शीघ्र टावर के समान दिखाई देने लगते हैं।
- इस अवस्था में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कभी-कभी बिजली चमक सकती है।
- **परिपक्व चरण:** वायु का ऊर्ध्वप्रवाह तूफान को ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है, साथ ही नीचे की तरफ वायु का प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ितझंझा से कभी-कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होता है।
- इसके कारण ओले गिरना, भारी बारिश होना, बार-बार बिजली गिरना, तेज हवाएं बहना और बवंडर आना आम विशेषताएं हैं।
- **समाप्ति चरण:** अंततः भारी वर्षा होती है और नीचे की तरफ वायु का प्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह पर हावी हो जाता है, जिससे समाप्ति का चरण शुरू होता है।

आर्थिक घटनाक्रम

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी।



मुख्य बिन्दु:

न्यूनतम समर्थन मूल्य

- परिभाषा:** यह एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार पूर्व-निर्धारित कीमत पर किसानों की फसलें खरीदकर उन्हें कीमत गिरने से सुरक्षा प्रदान करती है।
- सिफारिशें:** केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा इनकी सिफारिशें की जाती हैं।

--:17:--

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



- **अंतिम स्वीकृति:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा।
- **वैधानिक स्थिति:** MSP को कोई वैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।
- **शामिल फसलें:** 22 फसलें। इसके अतिरिक्त, तोरिया की MSP रेपसीड और सरसों के आधार पर तथा छिलका-रहित नारियल की MSP कोपरा की MSP के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- 14 खरीफ फसलें (जैसे- धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास)
- 6 रबी फसलें (जैसे- गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों, कुसुम)
- 2 वाणिज्यिक फसलें (कच्चा जूट, खोपरा)

UTKARSH

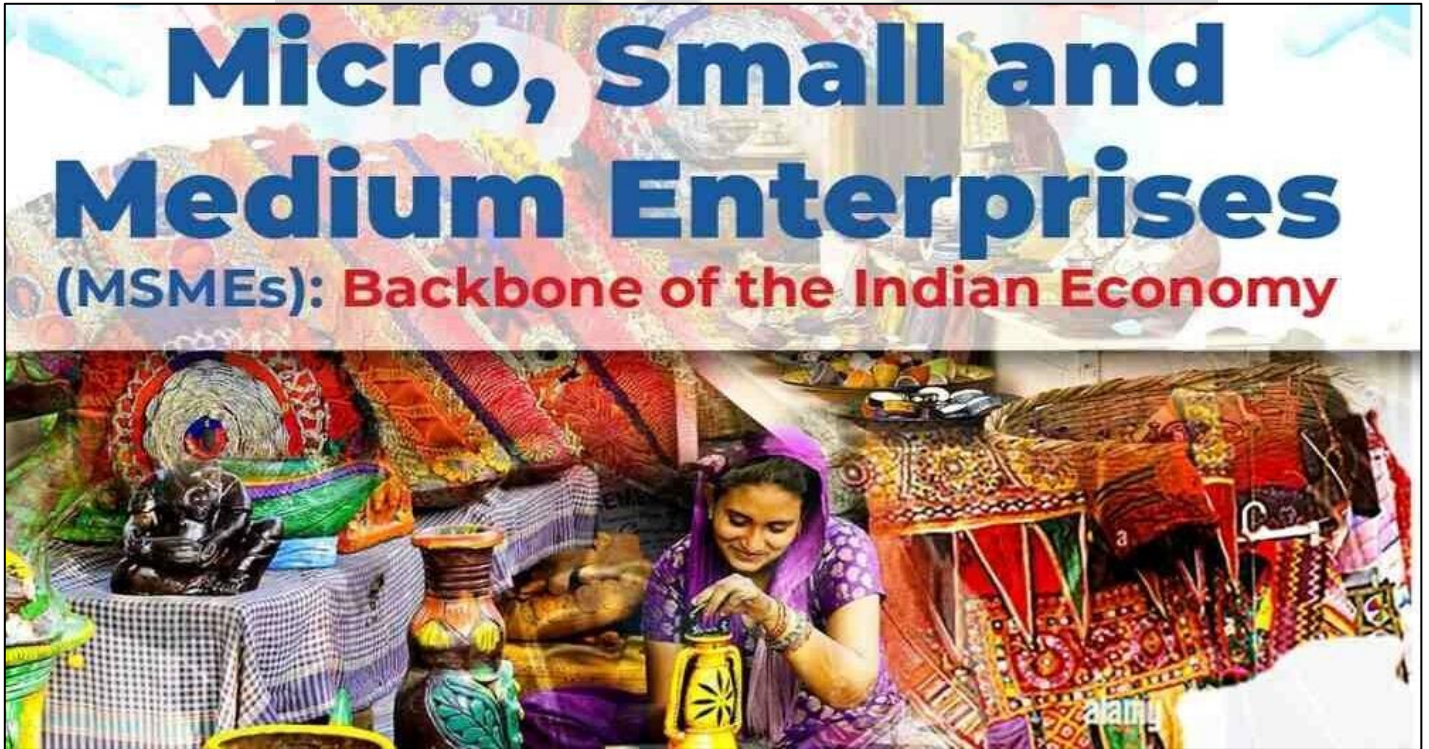
CIVIL
SERVICES

-:18:-

लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई): भारत के समावेशी विकास की रीढ़

चर्चा में क्यों?

- भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्यात और जमीनी स्तर पर उद्यमिता का एक प्रमुख चालक बन गया है।



मुख्य बिन्दु:

MSME

- लघु एवं मध्यम उद्यम वे उद्यम हैं जिन्हें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में MSME वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और उद्यमों को लाभ खोए बिना विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

Revision in Classification Criteria For MSME

| Category | Investment not exceeding (₹ in Crore) | (Revised) Investment not exceeding (₹ in Crore) | Turnover not exceeding (₹ in Crore) | (Revised) Turnover not exceeding (₹ in Crore) |
|----------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Micro | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
| Small | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Medium | 50 | 125 | 250 | 500 |

लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्यों महत्वपूर्ण हैं ?

- भारत की जीडीपी में लघु एवं मध्यम उद्यम का योगदान लगभग 31.1% है, कुल निर्यात में इनका हिस्सा 48.58% है और ये विनिर्माण उत्पादन का लगभग 35.4% उत्पन्न करते हैं।
- इस क्षेत्र में विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार गतिविधियों से जुड़े 7.47 करोड़ से अधिक उद्यम शामिल हैं।
- यह लगभग 32.8 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है, जिससे यह कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है।
- इनमें से अधिकांश उद्यम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होते हैं। ये स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को समर्थन देते हैं, गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **वित्त तक पहुँच:** लघु एवं मध्यम उद्यम, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम, संपार्श्विक आवश्यकताओं, सीमित ऋण इतिहास और ऋणदाताओं के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण महत्वपूर्ण ऋण अंतर का सामना करते हैं।
- **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** वैश्वीकरण और ई-कॉमर्स ने लघु एवं मध्यम उद्यमों को बड़े घरेलू खिलाड़ियों और सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा के सामने ला दिया है, विशेष रूप से वस्त्र, हस्तशिल्प और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में।

- **तकनीकी ज्ञान का अभाव:** लघु एवं मध्यम उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में - डिजिटल उपकरणों, स्वचालन और आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूकता और क्षमता की कमी से जूझ रहा है।
- **विपणन और नेटवर्किंग के अवसर:** सीमित बाजार संपर्क और खराब ब्रांड दृश्यता लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने से रोकते हैं।
- **नियामकीय बोझ:** श्रम, कराधान और पर्यावरण संबंधी नियमों में जटिल अनुपालन आवश्यकताएँ सीमित प्रशासनिक क्षमता वाले छोटे उद्यमों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** लघु एवं मध्यम उद्यम कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खासकर जब शहरी प्रवासन ग्रामीण विनिर्माण समूहों से श्रमिकों को दूर ले जाता है।
- **बाह्य झटकों के प्रति संवेदनशीलता:** जैसा कि कोविड-19 के दौरान प्रदर्शित हुआ, लघु एवं मध्यम उद्यमों - विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के पास माँग में अचानक बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता को सहन करने के लिए सीमित वित्तीय सुरक्षा कवच होता है।

सरकारी पहल

- **पीएम विश्वकर्मा:** 2023 में शुरू की गई यह योजना 2023-24 से 2027-28 तक के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसका उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर और उन्हें व्यापक बाजारों से जोड़कर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का उत्थान करना है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना:** लघु एवं लघु उद्यमों को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी के ऋण सुविधाओं के लिए ऋण गारंटी प्रदान करती है।

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:** इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और यह MSMEs के लिए एक निःशुल्क, कागज रहित और स्व-घोषित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:** एक ऋण-आधारित सब्सिडी योजना है जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करके स्वरोजगार को बढ़ावा देती है।
- **MSME हैकाथॉन 4.0 (2024):** नवाचार और इनक्यूबेशन के लिए 500 युवा उद्यमियों को 15 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान करके उनका समर्थन करता है।
- **MSME-TEAM योजना (2024):** एक व्यापार सक्षम पहल, जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग में 5 लाख एमएसई का समर्थन करती है।
- **खादी और ग्राम उद्योग:** सरकार खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें कोई राज्य घटक नहीं है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** यह योजना लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में सहायता करती है।

-:22:-

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

नई वैश्विक अव्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

चर्चा में क्यों?

- रणनीतिक स्वायत्तता से आशय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से वह विदेश नीति और रक्षा से जुड़े निर्णय बाहरी दबावों या गठबंधन संबंधी बाध्यताओं से मुक्त होकर स्वयं ले सके।

मुख्य बिन्दु:

- यह पृथक्तावाद या तटस्थता का पर्याय नहीं है, बल्कि लचीलापन, स्वतंत्रता तथा अपनी शर्तों पर विविध वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता को दर्शाता है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौतियाँ:

- विभाजित विश्व व्यवस्था:** अमेरिकी प्रभुत्व, चीन की आक्रामकता, और रूसी पुनरावलोकनवाद की वजह से विश्व आज कई पक्षों में विभाजित है।
- रूसी पुनरावलोकनवाद वास्तव में रूसी राष्ट्रपति की विदेश नीति की एक प्रमुख रणनीति है। इसका उद्देश्य शीत युद्ध के बाद बनी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलना, पश्चिमी देशों के प्रभाव को कमजोर करना और रूस के प्रभाव क्षेत्र को फिर से स्थापित करना है।
- पश्चिमी देशों का दबाव:** ऊर्जा एवं रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को लेकर विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा कूटनीतिक विरोध के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।
- चीन से चुनौती:** अमेरिका के साथ भारत की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को चीन के विरोध के रूप में देखा जाता है।

■ अन्य चुनौतियाँ:

- कमजोर होती अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ
- हाल के सैन्य संघर्षों में विधि के शासन के बजाय बल का प्रयोग को प्राथमिकता देना
- प्रौद्योगिकीय, डिजिटल और वित्तीय स्तरों पर देशों के बीच विभाजन
- संरक्षणवाद की ओर झुकाव, आदि।

रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए भारत के उपाय:

- **प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों का पुनर्संतुलन:** भारत अमेरिका के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है, साथ ही टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण आर्थिक संबंधों में संतुलन बनाए हुए है।
- **चीन के साथ संतुलनकारी नीति:** सीमा एवं कूटनीतिक स्तर पर तनावों के बावजूद भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है।
- **रूस के साथ मजबूत संबंध:** चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी और यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ने के बावजूद, रूस के साथ भारत अपने रक्षा और कूटनीतिक संबंध बनाए हुए है।
- **अलग-अलग देशों से रक्षा आयात करना:** इसके उदाहरण हैं; रूस के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का विकास, फ्रांस निर्मित मिराज 2000 लड़ाकू विमान, साथ ही इजरायल निर्मित हथियार जैसे SCALP-2000 बम।
- **व्यापार में विविधता लाना:** भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPAs) को वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ा रहा है।
- इसके अलावा, डिजिटल संप्रभुता, ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति शृंखला तथा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समावेशी विकास जैसे उपाय भारत की सामरिक स्वायत्तता को निरंतर बनाए रखने में सहायक होंगे।

थ्यूसीडाइड्स ट्रैप

चर्चा में क्यों?

- चीन के राष्ट्रपति ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" (Thucydides Trap) और पेलोपोनेसियन युद्ध का मुद्दा उठाया।



मुख्य बिन्दु:

थ्यूसीडाइड्स ट्रैप:

- **उत्पत्ति:** यह शब्दावली हार्वर्ड के राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन द्वारा गढ़ी गई थी।
- उन्होंने इसका नाम प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स के नाम पर रखा था, जिन्होंने पेलोपोनेसियन युद्ध का विवरण लिखा था।
- पेलोपोनेसियन युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच 431 ईसा पूर्व में शुरू हुआ एक लंबा युद्ध था।
- **अर्थ:** यह उस खतरे का वर्णन करता है जो तब उत्पन्न होता है, जब एक उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित (प्रमुख) शक्ति को विस्थापित करने की धमकी देती है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **वर्तमान में प्रासंगिकता:** इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका (स्थापित शक्ति) और चीन (उभरती वैश्विक शक्ति) जैसे जटिल और तनावपूर्ण भू-राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

--:25:--

'कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट' (CCRA)

चर्चा में क्यों?

- जापान में 'कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट' (CCRA) की पहली तिमाही बैठक के दौरान भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक CCDB के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।



COMMON CRITERIA RECOGNITION ARRANGEMENT

मुख्य बिन्दु:

CCDB:

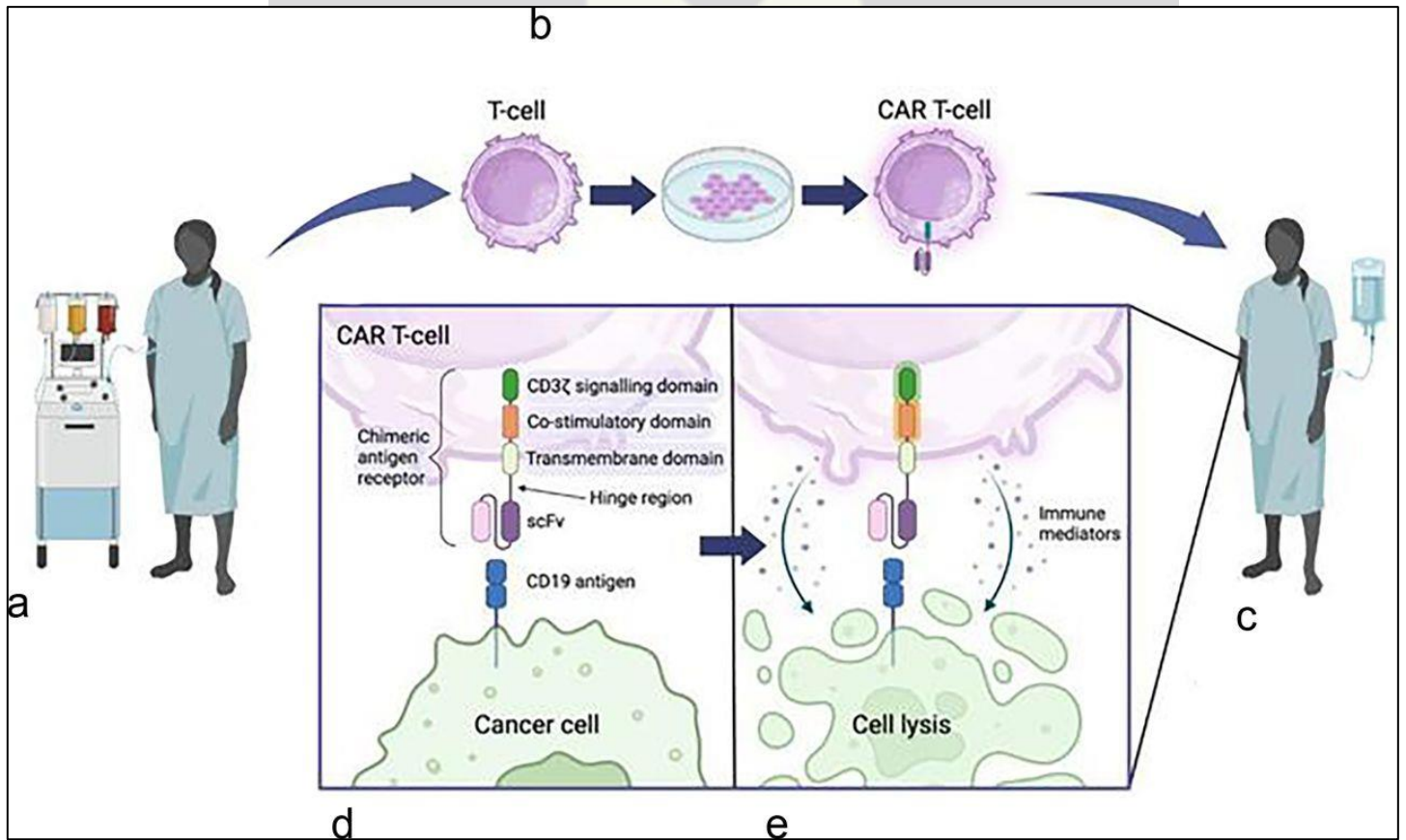
- यह CCRA के तकनीकी केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा 'कॉमन क्राइटेरिया' (CC) और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मूल्यांकन हेतु कॉमन मेथोडोलॉजी (CEM) की अंतरराष्ट्रीय कार्ययोजना का प्रबंधन करता है।
- CCRA एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो विभिन्न देशों के बीच IT सुरक्षा प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित करती है। इसमें प्रमाणन-अधिकृत करने वाले 20 देश तथा प्रमाणन-उपयोग करने वाले 18 देश शामिल हैं।
- **भारत और CCDB:** भारत 2013 से प्रमाण-पत्र अधिकृत करने वाले राष्ट्र के रूप में CCRA का सक्रिय सदस्य रहा है।
- भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मूल्यांकन के आधिकारिक प्रमाणन निकाय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और STQC निदेशालय कार्य करते हैं।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (CAR-T Cell) थेरेपी

📢 चर्चा में क्यों?

- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने भारत-सिंगापुर सहयोग ढाँचे के अंतर्गत मल्टीपल मायलोमा (लाइलाज रक्त कैंसर) के उपचार हेतु CAR-T सेल थेरेपी विकसित करने के लिए एक समझौता किया है।



📌 मुख्य बिन्दु:

CAR-T सेल थेरेपी

- CAR-T सेल थेरेपी को "लिविंग ड्रग" (सजीव औषधि) कहा जाता है क्योंकि इसमें रोगी की स्वयं की जीवित प्रतिरक्षा कोशिकाओं (T-कोशिकाओं) का उपयोग किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 16 May, 2026



- यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से T-कोशिकाओं को संशोधित करती है, और उन्हें कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली CAR-T कोशिकाओं में बदल देती है।
- T-कोशिकाएँ वे विशिष्ट कोशिकाएँ (श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार) होती हैं जिनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक (कोशिका-विषाक्तता) होता है। इसका अर्थ है अन्य कोशिकाओं को नष्ट करना।
- T-कोशिकाएँ रोगी के खून से ली जाती हैं और लैब में उनमें एक कृत्रिम रिसेप्टर (जिसे CAR कहते हैं) का जीन डालकर उनमें बदलाव किया जाता है और फिर उन्हें रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है।
- CAR ऐसे प्रोटीन होते हैं जो T-कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद किसी विशिष्ट प्रोटीन को पहचानने और उससे जुड़ने में सहायता करते हैं।

-:28:-